[श्रीमती सहोदराबाई राय]

यह भी कहना चाहती हूं कि अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आने वाला गेहूं पहले मध्य प्रदेश को देना चाहिए । अभी दो साल तक अमरीका का गेहूं बन्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम लोग मर जायेंगे । जब अगले दो सालों में हम अपनी स्थिति को सुधार लेंगे, तब पी० एल० 480 के गेहूं का मंगाना बन्द कर दिया जाये ।

हमारे देश में मुल्ला, मौलवी और पंडे आदि बहुत से बेकार लोग हैं । वे मुफ्त का पैसा खाते हैं और मजे करते हैं। पंडे लोग काशी, इलाहाबाद आदि तीर्थ स्थानों में यात्रियों को परेशान करते हैं । मेरा सुझाव ह कि उन लोगों को भी कृषि के काम में लगाया जाये, ताकि हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़े ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां बिजली के साधन उपलब्ध किये जाने चाहिएं, ताकि खेती और कल-कारखानों के लिए बिजली मिल सके । देहात में जो सरकारी पैसा बांटा जाता है, वह देहात में ही दस-दस गांवों के लिए एक जगह बांटा जाना चाहिए, जिस से हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट के कार्यालय की तरफ न भागना पड़े ।

मैं यह भी चाहती हूं कि कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी आदि सरकारी अधिकारियों को भी ठीक तरह से काम करने के आदेश दिये जाने चाहिएं । ये लोग काम में रोड़े अटकाते हैं । अगर कोई लोग हमारा तख्ता पलटेंगे, तो ये तहसीलदार, पटवारी आदि सरकारी कर्मचारी ही पलटेंगे, क्योंकि वे रिश्वत लिये बिना कोई काम नहीं करते हैं जिस से मेल-मुहब्बत हो, दोस्ती हो, जो पचास रुपये उन के हाथ में दे दे, वे सिर्फ उसी का काम करते हैं और दूसरों को कहते हैं "ब्लडी फूल" । जब तक ये प्रथायें खत्म नहीं होंगी, तब तक कृषि नहीं बढ़ सकती है ।

कृषि मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह देहात की तरफ निगाह रखें—वह केवल दिल्ली में ही न बैठे रहें, बल्कि देहात की तरफ भी जायें और देखें कि वहां क्या हालत है ।

हमारे मध्य प्रदेश में खेती का काम बहुत थोड़ा है, इसलिए काश्तकारों को बहुत कम काम मिलता है । इसी प्रकार मजदूरों के लिए भी कोई धन्धा नहीं है । इसलिए यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में नये उद्योग धंधे खोले जायें, जिस से हमारे यहां के मजदूरों को काम मिले । अगर सरकार हम लोगों को खेती के काम में सहायता देगी, तो हम उस को काफी गल्ला दे सकेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: The Minister will reply tomorrow. This debate will not be carried to tomorrow. Members who are anxious to speak will resume the debate after 5.30 today, after the half-hour discussion is over, and as long as Members are here, provided the quorum is not demanded, we will continue.

17.04 hrs.

*HINDUS DEBARRED FROM COMING TO INDIA

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत और पाकिस्तान, एक देश के दो भाग बने, तो

* Half-an hour discussion.

पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो हिन्दू या अल्प संख्यक जातियों के लोग रह गए थे, उन की संख्या कुल मिला कर 1,80 लाख के लगभग थी। इन 1,80 लाख लोगों के विषय में उस समय के हमारे नेताओं ने, जिन में गांधीजी, सरदार पटेल और नेहरू जी प्रमुख थे, विभिन्न स्थानों पर बार-बार इस आशय के वक्तव्य दिये कि इन लोगों के हितों की देख-रेख करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन उस के बाद जब पाकिस्तान में उन लोगों का धड़ाधड़ कत्ले-आम हुआ और वे वहां से निकाले गए, तो सरदार पटेल को एक बार बड़ी स्पष्ट और निर्भीक चेतावनी पाकिस्तान को देनी पड़ी। सरदार पटेल ने पाकिस्तान को यह कहा कि अगर धरती के बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान से अल्प संख्यकों की निकासी इसी प्रकार जारी रही, तो पाकिस्तान को यह चाहिए कि वह उन लोगों के बदले में उतने ही मुसलमान हिन्दुस्तान से अपने देश में ले ले और अगर वह उन को नहीं लेता है, तो फिर वह धरती का उतना हिस्सा हिन्दूस्तान को दे, जिस पर यहां आने वाले हिन्दुओं को बसाया जा सके।

सरदार पटेल को इस ललकार का परिणाम यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान में नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, उसकी ओर से इस समझौते की एक-एक शर्त का पूर्णतया पालन किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत पैक्ट का कहां तक पालन किया, उस का प्रमाण पर-राष्ट्र मंत्रालय द्वारा कुछ दिनों पहले जारी किये गए एक वक्तव्य से मिलता है। उस वक्तव्य में बताया गया है कि पिछले चौदह साल में, अर्थात् 1951 से अब तक, पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों की संख्या 1,80 लाख से घट कर केवल 90 लाख रह गई है, यानी वह आधे से भी कम बैठती है, जब कि इस की तुलना में मुसलमानों की संख्या पिछले चौदह साल में साढ़े तीन करोड़ से बढ़ कर पांच करोड़ के लगभग हो गई है।

पाकिस्तान की ओर से वहां के अल्प संख्यकों की जो जाति-हत्या की जा रही है, इस सम्बन्ध में उस की ओर से जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उस को देखते हुए हम को यह चाहिए था कि हम दुनिया को इन तथ्यों से अवगत कराते और बताते कि पाकिस्तान किस प्रकार की हरकतों पर उतर आया है।

पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि के आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि उस देश में 1951 और 1961 के बीच में कुल मिलाकर 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अकेले पूर्वी पाकिस्तान में (पश्चिमी पाकिस्तान के गैर-मुस्लिमों के आंकड़े कहीं उपलब्ध नहीं है) 1951 में गैर-मुस्लिमों की संख्या 99 लाख थी और 24 प्रतिशत के हिसाब से 1961 में उन की संख्या बढ़ कर 1,23 लाख के करीब पहुंचनी चाहिए थी, जब कि वास्तव में वह संख्या केवल 1,01 लाख के करीब पहुंची। इस का अर्थ यह है कि पाकिस्तान में कुल जनसंख्या की वृद्धि हुई 24 प्रतिशत और उस देश के हिन्दू, बौद्ध, ईसाई आदि गैरमुस्लिमों की जनसंख्या म वृद्धि हुई केवल 3 प्रतिशत।

इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपने यहां के गैर-मुस्लिमों को समाप्त करने के लिए जान बूझ कर ये उपाय बरते है कि या तो उन को वहां से निकाल दिया जाये, या उन की हत्या की जाये और या भारी मात्रा में उन का धर्म परिवर्तन किया जाये। पीछे इस प्रकार के समाचार बार-बार कानों में पड़ते रहे कि जब पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर उपद्रव हुए थे, तो नारायणगंज

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

से ढाका तक जो नदी पड़ती है, वह बराबर लाशों से पटी रही । पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के और भी स्थानों में इस प्रकार के दृश्य देखने को मिले ।

यह भी पता लगा है कि वहां पर जो छोटी जाति के लोग हैं, विशेष कर हरिजन और परिगणित जाति के उन का तो लाखों की संख्या में धर्म परिवर्तन कर दिया गया है । इसी प्रकार वहां के शासन का सहयोग पाकर हिन्दुओं के घरों से छोटी आयु की लड़कियों का अपहरण किया गया और उन को बलात दूसरे घरों में डाल दिया गया । इस प्रकार की घटनाओं के समाचार समय-समय पर भारत सरकार के कानों में पड़ते रहे हैं ।

अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद मुझे राजस्थान क्षेत्र में जाने का अवसर मिला । हमारे पुनर्वास मंत्री यहां पर मौजूद हैं । उन के कानों तक यह बात आई होगी कि जो हिन्दू परिवार वहां से उजड़ कर आए हैं विशेषकर उमरकोट और थर-पारकर जिलों के सोढा राजपूत और भील बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सरकारी अधिकारियों ने जब उन की आपबीती सुनी तो इस बात में कोई भी सन्देह नहीं रहा कि 1947 में पाकिस्तान के लोगों के द्वारा वहां के हिन्दुओं के साथ जो अमानुषिक व्यवहार और अत्याचार किये गए थे 1965 की इन घटनाओं ने उन को भी मात कर दिया । आप चल कर उन कैम्पों को देखिए । वहां पर आप वही दृश्य देखेंगे जो 1947 में लाहौर और कराची में देखे गए थे । कैसे औरतों के स्तन काटे गए कैसे पुरुषों को पेड़ों से बांध कर उन की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार की वीभत्स घटनायें हुई हैं जिन को मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता ।

इस के अतिरिक्त अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र सरदार कपूर सिंह ने इसी सदन में एक आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा था कि पंजाब के कुछ सीमावर्ती गांवों से करीब 70, 80 मासूम सिख बच्चियों को पाकिस्तानी उठा कर ले गए और भारत सरकार अभी तक यही कहती है कि उन के सम्बध में हम को पूरी जानकारी नहीं है और हम जानकारी ले रहे हैं ।

कुछ दिनों पहले पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में ऐसा समाचार मिला था कि छोटी आयु की लड़कियों को दूसरे देशों में ले जा कर बेचा गया जिस के बारे में सरकार की ओर से कहा गया कि हमें इस घटना का पता नहीं है । लेकिन पुनर्वास मंत्री और विदेश मंत्री को इस घटना का तो पता होगा कि जो हिन्दू पाकिस्तान से निकल कर भारत को आते थे, जब वे सीमा पर पहुंचते थे, तो अधिक उम्र के लोगों को तो भारतवर्ष में धकेल दिया जाता था, लेकिन उन की छोटी आयु की लड़कियों को उन से छीन लिया जाता था । किस हालत में आज वे बच्चियां होंगी ? वे कैसे दिन बिता रही होंगी ?

मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 1947 में पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनायें हो रही थीं, तो देहरादून में देश के एक बड़े भारी नेता ने कहा कि क्यों लोग व्यर्थ हो रोष में आते हैं । उन के साथ उन की लड़की भी थी । पीछे खड़े हुए पंजाब से उजड़ कर आए हुए एक भाई ने लड़की के मुंह पर हाथ लगा दिया । उन नेताजी को इतना क्रोध आया कि तपाक से उन्होंने उस के मुंह पर एक चपत दे मारा । वह जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि महाराज, मैं

तो यह बताना चाहता था कि आप की लड़की के मुंह पर हाथ लगा तब तो आप को इतना क्रोध आया, लेकिन जिन की लड़कियां पाकिस्तान में रह गई हैं, जिन की आंखों के सामने उन की लड़कियों के साथ वीभत्स कांड हुए हैं उन के दिल पर हाथ रख कर देखिये कि उन के हृदयों पर क्या बीत रही होगी ? जो परिवार उजड़ कर यहां आ गये और उन की लड़कियां वहां पर रह गईं, वह लड़कियां वहां पर किस भयंकर स्थिति में होंगी । आप थोड़ा उस कारुणिक परिस्थिति की कल्पना तो कीजिये ।

इस प्रश्न पर जो मैं ने आधे घंटे की चर्चा उठाई है वह पूर्वी पाकिस्तान के जसोर और फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट से जो एक हजार हिन्दू परिवार अपने प्रमाण पत्र भारतीय हाई कमीशन के कार्यालय से विधिवत् ले कर आ रहे थे, और जिन को रोक लिया गया, उन के सम्बन्ध में है । भारत सरकार से पूछा कि क्या उसे इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि आज वह किस अवस्था में हैं, तो हमारी सरकार ने यह कह कर अपना पीछा छुड़ा लिया कि वहां हमारी कोई संचार व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार के समाचार आदान-प्रदान के कोई साधन नहीं हैं इसलिये हमें पता नहीं कि उन की स्थिति क्या है । अभी कल ही कलकत्ते के "युगान्तर" में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि हमारी एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन, श्री ए० सी० गुह, ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है, और यू० एन० आई० ने उस न्यूज को दिया है । उस में उन्होंने कहा है कि पांच हजार हिन्दू आज भी ऐसे हैं जो इन्हीं परिस्थितियों में वहां नजरबन्द हैं । उन्होंने कहा है कि या तो रेड क्रास जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से उन की जांच कराई जाये या कोई और विशेष व्यवस्था की जाय और पूर्वी पाकिस्तान में जो दुर्व्यवस्था चल रही है उस की जानकारी विशेष प्रकार से ली जाये कि वहां क्या हो रहा है। उमरकोट और थरपारकर में जो लाखों की संख्या में हिन्दू हैं, सिन्ध के इलाके में और राजस्थान की सीमा पर उन सोढा राजपूत और भीलों को वहां शहर से निकाल कर कैंपों में डाला गया है और वे वहां पर नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं । लेकिन भारत सरकार यह कहती है कि हमें उन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है । हमारे देश में इतने देशों के राजदूत रहते हैं हम कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के भी सदस्य हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों भारत सरकार उन से इस प्रकार की बातें नहीं कहती कि वे वहां जायें और जा कर वस्तु स्थिति का पता लगायें ।

पाकिस्तान इस से उल्टे भी कुछ दूसरे काम कर रहा है । दूसरे काम यह कि वह भारी मात्रा में , लाखों की तादाद में हमारे यहां मुसलमानों को भेज रहा है। अभी भी असम के अन्दर दस लाख से अधिक मुसलमानों का आगमन हुआ । आज वह असम को दूसरा काश्मीर बनाना चाहता है और असम की स्थिति को बिगाड़ना चाहता है । आप मुझे इन शब्दों को कहने की आज्ञा दीजिये कि इस में असम के कुछ उन लोगों का हाथ है जो कि वहां पर जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं । विदेश मंत्रालय को शायद इस बात की जानकारी होगी । मैं इस प्रकरण को यहां विस्तार से नहीं छेड़ना चाहता । 1961 के सेन्सस की जो रिपोर्ट है उस के अनुसार जो पाकिस्तान से लगे हुए कुछ जिले हैं उन में से कई जिले इस प्रकार के हैं जहां कुल मिला कर जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वह 21 और 24 प्रतिशत के मध्य में है लेकिन राजस्थान के पाकिस्तान से लगे हुए कुछ ऐसे जिले और स्थान हैं, जैसे गंगानगर, बीकानेर और

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

बाड़मेर, जहां मुसलमानों की संख्या कहीं 55 प्रतिशत बढ़ी है, कहीं 85 प्रतिशत बढ़ी है, कहीं शत प्रतिशत भी बढ़ी है, कहीं 200 प्रतिशत बढ़ी है और कहीं कहीं हजार हजार प्रतिशत बढ़ी है। आप सन् 1961 की जनगणना रिपोर्ट को उठा कर देखिये तो आप को उस के आंकड़ों से पता चलेगा कि भारतवर्ष में दस वर्षों में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह 22 और 24 के मध्य में है लेकिन भारत में जो मुसलमानों की जन संख्या में वृद्धि हुई है वह 38 प्रतिशत के हिसाब से हुई है। क्या इस के पीछे कोई कारण नहीं है। भारत सरकार ने यह बात जानने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया कि पाकिस्तान की नीति क्या है।

खान अब्दुल गफ्फार खां को एक पत्र श्री यमुना लाल बजाज की पुत्री मदालसा बहन ने, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे राजदूत की धर्मपत्नी हैं, लिखा था। उस पत्र के उत्तर में खान अब्दुल गफ्फार खां ने एक पत्र भेजा है जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उस में उन्होंने लिखा है, अगर हिन्दुस्तान की सरकार यह सोचती है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ छेड़ छाड़ कर के वह पाकिस्तान का पागलपन बन्द कर सकेगी तो हिन्दुस्तान की सरकार बड़ी भूल में है। पाकिस्तान से निपटने का तो एक ही प्रकार है कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही सदा के लिये खत्म किया जाय। तभी हिन्दुस्तान शान्ति के साथ बैठ सकता है। जहां लाखों व्यक्तियों का कत्ले आम हुआ है, जहां लाखों लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक घटनायें हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा अपना इतिहास तो उठा कर देखिये। एक सती की आंखों से निकले हुए आंसू ने आज से हजारों साल पहले रावण की लंका को समाप्त कर दिया था, पांच हजार साल पहले एक देवी द्रोपदी की आंखों से निकले हुए आंसू ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अट्ठारह दिनों में अट्ठारह अक्षौहिणी सेनाओं को समाप्त कर दिया। शायद मैं बहुत पुरानी बात पर चला गया। मैं कल की घटना आप को बतलाता हूं कि स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का परिणाम क्या क्या हुआ है। मुसोलिनी की लाश में मरने के बाद एक महिला ने जाकर रिवाल्वर की तीन गोलियां निकालीं, हिटलर का अन्त भी इसी प्रकार का हुआ, जापान के तोजो की सेना ने औरतों के साथ जो व्यवहार किया उस का परिणाम तोजो के साथ क्या हुआ? मैं सरदार स्वर्ण सिंह को याद दिलाना चाहता हूं यह इतिहास और कहना चाहता हूं कि अगर नारी की आंखों से निकले हुए आंसू ने रावण की लंका को नहीं रहने दिया, दुर्योधन नहीं रह सका, मुसोलिनी, हिटलर और तोजो नहीं रह सके, तो नारी की आंखों से निकले आंसुओं से अय्यूब और भुट्टो भी नहीं रह सकेंगे, उन का शासन भी नहीं रह सकेगा। इसलिये वह निर्भय हो कर निर्णय लें। जो स्थिति हमारे साथ चल रही है उस के सम्बन्ध में कम से कम इतना तो अवश्य करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवीय अधिकारों के संरक्षण का घोषणा पत्र है उस के अन्तर्गत सारी बातों को सुरक्षा परिषद् के सामने रक्खें तो कि पाकिस्तान ने पिछले सत्तरह सालों में किस प्रकार से लाखों की तादाद में वहां लोगों का कत्ले आम किया है, लाखों की तादाद में लोगों का धर्म परिवर्तन किया है और किस किस प्रकार से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। दुनिया जाने तो सही कि वहां क्या हो रहा है। आज विश्व के जनमत को प्रभावित करने के लिये हमको अपना केस दुनिया के सामने रखना चाहिये।

तीसरी चीज यह कि हम को इस महाविनाश को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिये और चौथी चीज यह कि आज जो स्थिति है उस का किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा या जो आप के मित्र राष्ट्र इस प्रकार के हैं जिन के साथ हमारे घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध हैं उन के द्वारा वस्तु स्थिति का पता लगायें ताकि यह जो भयंकर स्थिति अब चल रही है वह ज्यादा देर तक न चल सके ।

मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्री इस बात की गम्भीरता को समझेंगे और इस के निराकरण का कोई उपाय सोचेंगे ।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Taking into account the unprecedented atrocities and acts of aggression and genocide committed on the non-Muslims in East Pakistan, may I know whether the Government has evolved a scheme to shift the entire non-Muslim population to India and demand compensation from Pakistan for the property left behind by them?

श्री बड़े (खारगोन) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो आप के सामने और हाउस के सामने वर्णन किया है उस से दर्दनाक और शर्मनाक बात और नहीं हो सकती । शासन ने भी इस को अनुभव किया होगा और हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बनने से हमारी स्त्रियों का कितना अपमान हुआ, हमारी छोटी छोटी महिलाओं की वहां कोई इज्जत नहीं रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासन को यह मालूम है कि जो पांच हजार नजरबन्द भारतीय वहां पर हैं उन को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिये विवश किया जा रहा है । इसी तरह से मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो सोडा. . .

Mr. Deputy-Speaker: Only one question please.

Shri Bade: Only one question, (a) and (b).

Mr. Deputy-Speaker: Only (a).

Shri Bade: That is (a).

जो सोडा राजपूत आये हैं उन की महिलाओं का अपहरण वहां हुआ है । वे आप से शस्त्र मांग रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह बात सच है या नहीं । इसी तरह से असम बार्डर पर कोई पिछले दो महीनों से ईसाई, बौद्ध और हिन्दू इस तरफ आ रहे हैं, क्या यह शासन की जानकारी में है ।

Mr. Deputy-Speaker: Only one question need be answered.

Shri Bade: This is only one question.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मैं जानना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या राजस्थान के वासियों ने सरकार से ऐसी मांग की है कि उन को हथियार दिये जायें और वह अपनी रक्षा कर लेंगे तथा उन की जो बहन बेटियां पाकिस्तान के अधिकार में हैं उन को वह छीन लायेंगे । क्या सरकार ने इस के बारे में कोई विचार किया है ?

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad): May I know as to what prevents the Government from raising this question in international forums if it is not able to intervene effectively and protect the minorities against the barbarities there in Pakistan?

Shri S. C. Samanta (Tamluk): Is it true that the Pakistan Government is following a sure but slow process of converting Hindus in Pakistan; if so, what steps have Government taken or propose to take in the matter?

Shri B. K. Das (Contai): In view of the fact that communication has

[Shri B. K. Das]

been re-established, has it been possible for Government to ascertain whether those who have been granted migration certificates are allowed now to come freely and, in cases of detention, whether the time of the migration certificate has been extended?

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मैं जानना चाहता हूं कि सन् 1947 में जो हिन्दू थे वह कितनी संख्या में थे और उस के हिसाब से अब तक उन की कितनी जन संख्या बढ़नी चाहिये थी । और अगर नहीं बढ़ी है तो इस का क्या कारण है, क्या सरकार ने कभी इस का पता लगाया ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): Mr. Deputy-Speaker, Sir......

श्री हुकम चन्द कछवाय : या सरकार इन सारे मामलों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ले जाने का विचार रखती है ?

Shri Swaran Singh: I have every sympathy for the feelings of concern that have been expressed on the floor of the House by Shri Prakash Vir Shastri and also by other hon. Members because the questions that they have asked also point in the same direction, highlighting the sense of insecurity that is being felt by the members of the minority community in Pakistan. This is a problem which has been discussed from time to time on the floor of the House. In a matter like this, where if the normal responsibility that any Government has towards every citizen living in that country is not honoured, if that responsibility is not discharged, then all these ugly facets of the situation develop and this is precisely what has happened to the minorities in Pakistan.

It is a matter of history that very few persons could stay on in West Pakistan soon after Independence. The conditions were such that most of the Hindus and Sikhs from Punjab, North West Frontier Province and also from Sind found their life so intolerable and there was such a sense of insecurity that they could not stay on there and they had to come over to India. In East Pakistan, in the beginning, though the conditions were very much disturbed and the minorities felt insecure there comparatively the acts of violence were not of the same order as those that occurred, unfortunately, in West Pakistan and so a very large number of our Hindu brethren continued to stay on in East Pakistan. Even those who stayed on never had that sense of security and never had that feeling of equality of citizenship notwithstanding the various agreements.

Shri Prakash Vir Shastri has referred to the Nehru-Liaquat Pact. I have no hesitation in saying that the responsibilities that had been taken upon themselves by the Government of Pakistan under the Nehru-Liaquat Pact have, unfortunately, never been honoured and there has been a continued sense of insecurity and mounting pressure on the minorities in that part. We know it very much to our cost that when things became so hot that non-Muslims there did not find it easy to stay on even under those conditions in which they had, at the best, a second-class citizenship, not a sense of equality that the predominant community or the ruling community had there, even under that inferior citizenship, they sometimes found it too hot to stay on there, and we had to face the spectacle of lakhs of people coming over to our side. In fact, my colleague, Shri Mahavir Tyagi, knows the circumstances in which these people have come over, the hardship that they had experienced and the destitude condition in which they cross over to Indian territory. He has organised various camps and several rehabilitation schemes to enable these uprooted people to find their feet in India.

So far as the analysis is concerned, I entirely agree with the analysis that has been put forward by several hon. Members. How do we deal with this situation? I was trying to find out whether there was any new approach to this problem. Implicit in the speeches of the hon. Members were the suggestions that we should take this whole issue to the international forum and various other formus—this is really the central point that has been urged by several hon. Members, including the hon. Member who has raised this discussion. We have given a very careful consideration to this matter. Seeing the experience that we and several other countries have of the functioning of international organizations, we are firmly of the opinion that, whereas in an international forum you may have the spectacle of allegations and counter-allegations being hurled at each other, there is very little that any international organisation can do apart from its appearance in several documents that might be produced by the international bodies. Experience elsewhere also indicates that the international community has not been able to find an answer to the difficulties that are experienced by any group of people if the Governments of those countries do not discharge the responsibilities that they owe to their own citizens. This is an unfortunate situation. This is really a situation in which the international community has not been able to find any answer to the troubles. It is true that the international community in several sectors has come in a marginal way to look after the refugees, to give them some succour, to give them some relief in the form of medicine or clothes or even doles; but that is not the point which bothers us. Can the international community do anything to create conditions in which minorities in any country might feel reassured. Excepting the international public opinion which might have some effect upon the rules of that country, the international community has not got any instruments by which it can effectively bring about a state of affairs in which the minorities in any country might feel reassured? This is a circumstance which we should accept as a hard fact of life. I would like to remind the hon. Members that there are several aspects to this. For instance, whatever may be our performance in this, our performance is very creditable and we can take just pride and satisfaction in the thought that we, in our country, have given equality of status to all persons, whatever religion they might belong to. We have got persons from minority communities occupying highly responsible positions in our political life, in our social life and in our economic life. But that is not the position in Pakistan. There are not people occupying even in their governmental set-up responsible positions; there are no prospects for their advancement. These are hard facts of life, I would only like to say that, to keep up this propaganda, Pakistan also continues to say that we, in India, are not treating our minorities well; they talk of evictions of Muslims from this part; sometimes they talk about Kashmir—the allegations that they recently made in the Security Council. I would like to remind the hon. Members of this House that we have taken a very firm line that these matters as to how we treat our minorities in India are matters which are entirely our own. Even the treatment of people in Kashmir is entirely a matter for the Jammu and Kashmir Government. We are confident that even if we have to explain to anybody we can explain it well because our record is clean. We have nothing to hide. But still we have adhered to this principle that these are internal matters in which no international community has got any right to ask us in India as to how we treat people living in any part of India, whether it is in Kashmir or any other part.

Shri S. N. Chaturvedi: It is a question of human rights. On that basis this matter can be raised. South Africa is another example, where this question had been raised.

Shri Swaran Singh: Even in South Africa I would like the hon. Member to remember one thing. What has the international community been able to do to the Africans there in South Africa? The point is no doubt raised, and speeches are made and some documents are produced, but what relief has the African in South Africa got so far? Ultimately, it may have to be a major conflict, and some signs of it are appearing to be inherent in the Rhodesian struggle. So, these are matters which we have to carefully weigh. We should always resist the temptation of taking to the international forums matters which are essentially within our internal jurisdiction. It is not clear to me what type of relief we expect the international community to give. You will find that the international community is not able and is not competent to give any relief. So, let us not in our exuberance, by pinning hope on something which does not exist in actual reality, try to work ourselves up to a mood in which we might be looking to others for finding solution to our problems. These are difficult problems for which we shall have to find our own solutions, according to the best of our capacity. The more I have been able to apply my mind to it, the more and more I feel convinced that in the international forums there might be allegations and counter-allegations, but I do not see any good or any useful result or any practical result coming out of our taking these matters to any international forums.

Shri Bade: The sum and substance of the hon. Minister's speech is....

Shri Swaran Singh: Let not my hon. friend try to sum up. I can sum it up myself.

Shri Bade: The sum and substance is that there is no remedy?

Shri Swaran Singh: The remedy is to continue to insist that it is their responsibility and that they will have to honour their responsibility just as it is our own responsibility on our side to look after the minorities here, and in respect of whatever we do on that, we are not answerable to any outsider for that. Let us be quite clear on that issue. It is not on an outside authority insisting that we should look after our minorities well that we are looking after them but because we think that that is the right thing to do, and we shall have to insist that Pakistan also does that thing, although I must confess that in the past we have not been able to succeed in our efforts in that connection.

Shri P. R. Chakraverti has put the question whether we should think of shifting the entire non-Muslim population to India. I think that it is a very desperate suggestion to make. We should not entertain any such idea and we should not think in those terms at all.

श्री हुकम चन्द कछवाय : वे वैसे मार मार कर भगा देंगे ।

Shri Swaran Singh: The hon. Member had asked me to answer and I am answering it. So, what is the use of shouting?

Shri P. R. Chakraverti: What about demanding compensation from the Pakistan Government?

Shri Swaran Singh: My hon. friend is talking of compensation for this. But we have got crores and crores of rupees which Pakistan still owes us, even on the refugee property or evacuee property of Hindus and Sikhs, which has been left over in West Pakistan. Who is to give us that money and wherefrom have we to get that money?

श्री हुकम चन्द कछवाय : उनके खिलाफ हथियार का इस्तेमाल कीजिए, तभी वे मानेंगे ।

Shri Swaran Singh: In terms of money you can never measure the

great misery and the great hardship to which human beings are put when they are uprooted. It is wrong to think in terms of money as if everything can be converted in terms of money. It cannot be converted into money, and we should give up the idea of commercialising everything that we can think of; I think that that is a mentality which we should give up and we should not cling to those ideas.

Shri Bade had asked whether there were still some people, some Hindus who had been interned there. He said *'Panch hazar nazarbandh hain'*.

It is true that at the time of the conflict, certain people had been interned by Pakistan. We had also interned certain people here. When the situation improves a little, we will take steps to repatriate our people from the other side. We are willing to repatriate the Pakistani nationals from our side.

One or two questions have been put as to what is our response to the demand of people living on the border to give them arms. Generally the approach of the State governments is—as you know, this is a State subject—this; they have been looking into that aspect and I know certain States where they have taken some steps to increase the defence potential of those areas by giving arms to people who can use those arms effectively. This is a matter which is receiving the attention of the State governments concerned and I am sure, depending on local conditions on each border, they will take appropriate steps.

The State of Assam has been mentioned. The question of infiltration into Assam has been receiving the attention of this House from time to time. I would not go into details. I would only like to mention that steps have been taken by the Assam Government in consultation with the Government of India to initiate proceedings which ultimately have resulted in the Assam Government succeeding in sending across the border the illegal infiltrants who had come from Pakistan into our territory....

Shri Bade: That is wrong. They have seized places on the border.

Shri Swaran Singh: ....That has to a large extent effectively dealt with that aspect. Something more has to be done, and I am sure that the Assam Government will take further steps in this connection.

One question has been asked by several hon. Members in which they have given the population of Hindus at the time of partition and asked why it has decreased. The reply is quite obvious because very large numbers have migrated into India. As you know, 40-50 lakh people have come out from West Pakistan alone. Even from East Pakistan, over several occasions we have received lakhs and lakhs of people. So it is quite obvious that the number there has not kept to the normal level on account of the sense of insecurity that is felt by non-Muslims in East Pakistan with the result that from time to time they have come over to this side.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया गया है ।

Shri Swaran Singh: Maybe there are cases of forcible conversion also which has been brought to our notice. That also may be partially responsible. The big segment is of those who have migrated. If you add up the figures, you will get the total which should work out according to your statistics. That is really the basic thing that is responsible for the decrease of the population there.

This is all I have to say. We have every sympathy for those people there. We continue to do our best. We know our limitations and within those limitations, everything that could be done is being done and will continue to be done.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, इससे बिल्कुल संतोष नहीं है । यह नपुंसकता की नीति अपना रहे हैं ।